

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
अवमानना (आपराधिक) वाद सं०-०५/२०१३

जैनब अली

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डी०एन० पटेल
माननीय न्यायमूर्ति श्री पी० पी० भट्ट

आवेदक की ओर से : श्री अरविंद कुमार चौधरी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री सुचेन्द्र प्रसाद, ए०पी०पी० ।

०६/दिनांक:१७वीं दिसंबर, २०१३

मौखिक आदेश:

डी० एन० पटेल, न्याया० के अनुसार

1. आवेदक के अधिवक्ता का इस मामले पर विस्तार से बहस करने से पहले, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जोरदार पूर्वक यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, १९७१ की धारा १५ के तहत आवेदक को सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं है जब तक कि झारखण्ड राज्य के एडवोकेट जनरल से सहमति नहीं ली जाती है और रिकॉर्ड पर कोई विशिष्ट सहमति उपलब्ध नहीं है, इसलिए, यह आपराधिक अवमानना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
2. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह इस आपराधिक अवमानना याचिका को प्रचालित नहीं कर रहा है, लेकिन, उपयुक्त फोरम के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए आवेदक अपना अधिकार सुरक्षित रख सकता है।
3. उचित फोरम के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए आवेदक को छूट प्रदान करते हुए, इस आपराधिक अवमानना याचिका को, इस स्तर पर, प्रचालित नहीं करने के कारण निष्पादित किया जाता है।

(डी० एन० पटेल, न्याया०)

(पी० पी० भट्ट, न्याया०)